PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Monday 15th December 2014, Page: 14
Width: 14.30 cms, Height: 10.92 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-15.29.129

विस्तार : प्रोत्साहन पाने वाले उद्योगों की सूची में नए क्षेत्र होंगे शामिल

मेक इन इंडिया का बढ़ेगा दायरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मैन्यूफैक्चरिंग की मौजूदा रफ्तार में भले ही अभी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा हो, लेकिन सरकार मान रही है कि मेक इन इंडिया अभियान आने वाले समय में देश की मैन्यूफैक्चरिंग में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे देखते हुए सरकार इस अभियान के तहत प्रोत्साहन पाने वाले उद्योगों की सूची का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस सूची में पांच नए उद्योगों को शामिल किए जाने की संभावना बन रही है।

जिन उद्योगों को मेक इन इंडिया के तहत प्रोत्साहन पाने वालों की सूची में शामिल किए जाने की उम्मीद है, उनमें रत्न व आभूषण (जेम एंड ज्वैलरी) और लघु व मझोले उद्योगों की श्रेणी में आने वाली इकाइयां हो सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों उद्योगों में निवेश को लेकर घरेलू और विदेशी दोनों स्तर पर अधिक रुचि दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में जब

- सूची में पांच नए उद्योगों को शामिल किए जाने की संभावना बनी
- रत्न और आभूषण तथा एसएमई पर किया जा रहा है विचार

मेक इन इंडिया अभियान शुरू करने की घोषणा की थी तब प्रोत्साहन पाने वाले उद्योगों की सूची में 25 क्षेत्र शामिल थे। इनमें फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एविएशन, माइनिंग, केमिकल आदि क्षेत्रों को रखा गया था। माना गया कि मौजूदा वक्त में इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना है और इन क्षेत्रों के भारत में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए ही जेम एंड ज्वैलरी और लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) जैसे सेक्टरों को इनमें शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

इन सभी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले संकेतक खोजने का काम जारी है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय ढूंढने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का इरादा वर्ष 2022 तक मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी को मौजूदा 16-17 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद पर लाने का है। इस दिशा में औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) निवेश आकर्षित करने और देश में कारोबार करना आसान बनाने के संबंध में कई कदम उठा भी चुका है।

6